(c) what steps have been taken to overcome the situation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) Exports to USSR take place in terms of the Trade Protocol signed every year. According to information available with the Tabacco Board, the quantities of tobacco provided for export in the Trade Protocol for 1991 have already been exported. As regards 1992, the Annual Trade Protocol is yet to be finalised.

भारत की निर्यात और आयात नीति

*378. श्री ईश दत्त यादव: क्या वाणिज्य मंत्री 26 नवम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 365 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत की निर्यात और आयात नीति भुगतान-संतुलन की समस्या का सामना करने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात और आयात नीति में विगत पांच वर्षों में कितनी बार बदलाव किये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) और (ख) विगत 10 वर्षों में सरकार ने निर्यात बढ़ाने और गैर-जरूरी आयात को कम करने के उद्देश्य से निर्यात-आयात नीति तैयार की। एक अर्थक्षम भुगतान सन्तुलन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक्सिम नीति और हमारी परोक्ष-लाभ नीति जिसमें कामगारों के लाभ, पर्यटन और ब्याज भुगतान शामिल हैं, उससे यह अपेक्षा थी कि उससे हमारे भुगतान-सन्तुलन की स्थिति नियंत्रण योग्य हो जाएगी। किन्तु, हम उसमें अधिक सफल नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा विदेशी ऋण अब लगभग 70 बिलियन अमरीकी डालर बकाया रहता है। विगत 10 वर्षों (1980-81 से 1989-90) में व्यापार घाटा 58 बिलियन अमरीकी डालर का रहा है। वर्ष 1990-91 में व्यापार घाटा 5.9 बिलियन अमरीकी डालर का रहा।

नई सरकार ने सत्ता में आने के तुरन्त बाद जुलाई तथा अगस्त, 1991 में आयात-निर्यात नीति में भारी संशोधन किए। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार घाटे में काफी गिरावट आई है। अप्रैल—सितम्बर, 1990 की अवधि में 2.4 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का व्यापार घाटा हुआ था जो अप्रैल—सितम्बर, 1991 की अवधि में घटकर 1.0 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का रह गया। यद्यपि विस्तृत आयात-निर्यात नीति की घोषणा की गई है फिर भी, व्यापार-वातावरण को और अधिक प्रेरणादायक बनाने और भुगतान-सन्तुलन की स्थिति को और अधिक अर्थक्षम बनाने के वास्ते आयात कम करने के लिए समय-समय पर छोटे-छोटे परिवर्तन किए जाते हैं।

Setting up of a High Court bench in Western U.P.

*379. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Government has discussed the matter for establishment of a High Court bench in Western Uttar Pradesh with the present state Government;

(b) if so, what has been the reaction of Government of Uttar Pradesh thereto; and

(c) by when the matter would be finalised?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY): (a) Recommendations of the Jaswant Singh Commission for setting up of Benches of Allahabad High Court in Western Uttar Pradesh were, referred to the Government of Uttar Pradesh in October, 1986 for their views and comments, in consultation with the Chief Justice of the High Court.

(b) No specific, complete proposal has so far been received from the Government of Uttar Pradesh.

(c) The matter can be finalised by the Central Government only if a specific and complete proposal is received from the State Government.

Setting up Power Plant in Tamil Nadu by Australia

*380. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of